

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :- 09/2020

निर्णय दिनांक :- 26.02.2021

प्रार्थी :-

खीमाराम पुत्र जसा आयु-वयस्क, जाति-मेणा निवासी-सादडी तहसील-देसूरी
जिला-पाली (राज)

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. भूराराम पुत्र किसना जाति-मेणा आयु-वयस्क
2. वेनाराम पुत्र किसना जाति-मेणा आयु-वयस्क
निवासीगण-सादडी तहसील-देसूरी जिला-पाली

(- :वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 92ए राजस्थान काश्तकारी)

अधिनियम:-

-:प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित
धारा 151 सीपीसी :-

उपस्थिति:-


1. श्री शेषाराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक :-26.02.2021

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि-प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम सादडी 2 पटवार हल्का-सादडी चक 2 तहसील-देसूरी जिला-पाली में प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण एव् दीगर सह खातेदारो की सयुक्त खातेदारी एवम् आधिपत्य की आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5186, 5188 कुल खसरे-9 कुल रकबा 3.2100 हैक्टर कुल लगान रूपये 54.57 विद्यमान है।




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 0




कमला पेज(2) : निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0), देसूरी निर्णय राजस्व विधि संख्या-09/2020 घास-212 आर.टी.
एवं-प्रार्थी खीमाराम बनाम- अप्रार्थी गुराराम व अन्य

वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य का 3/32 वॉ हिस्सा विद्यमान है एवम् वादग्रस्त आराजियात में दर्ज खातेदार होजी पत्नी जसा प्रार्थी की माता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवम् मृत होजी का विधिक वारिस प्रार्थी ही है, जिसके अलावा इसका अन्य कोई वारिस नहीं हैं जिससे उक्त वादग्रस्त आराजियात में विद्यमान प्रार्थी का माता मृत होजी की खातेदारी का 1/32 वां हिस्सा कानूनन प्रार्थी में निहित हुआ। इस वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का कुल मिला कर $3/32+1/32=1/8$ वां हिस्सा हिस्सा एवम् अप्रार्थी संख्या 1 का $1/4$ व $1/8$ हिस्सा एवम् अप्रार्थी संख्या 2 का $1/24$ हिस्सा संयुक्त खातेदारी आधिपत्य का विद्यमान हैं।

यह है कि वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं हुआ है। जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी हिस्से की कृषि भूमि में नाजायज दखलन्दाजी करते हैं एवम् आवाजाही में नाजायज दखल रोक टोक करते हैं एवम् टण्टा फसाद करते हैं। जिससे वादग्रस्त आराजी आराजी में प्रार्थी स्वयं का 3/32 वा हिस्सा एवम् अपनी माता मृत होजी पत्नि जसा के नाम दर्ज 1/32 वा हिस्सा कुल मिला कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का $1/8$ वा हिस्स घोषित का पृथक बंट करवाना चाहता है, जिसका प्रार्थी को विधिक अधिकार प्राप्त है।

यह है कि मूल वाद के निर्णय में लम्बा समय लगेगा जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी के $1/8$ वा हिस्सा की भूमि में प्रार्थी के कब्जा में एवम् आवाजाही में नाजायज दखल, रोक टोक रहे हैं एवम् अपनी मनमर्जी से अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जोर जबरदस्ती काश्त करने पर आमामादा है एवम् बिना विभाजन के भूमि विशेष को अन्यत्र खुर्दबुर्द करने पर आमामादा है जिसका अप्रार्थीगण को कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है एवम् यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उसकी खातेदारी हिस्से की भूमि पर काश्त करने में एवम् आवाजाही में रोक टोक करने पर प्रार्थी काश्त से वंचित हो जायेगा एवम् प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवम् प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो से नहीं की जा सकेगी एवम् अनावश्यक वाद विवाद बढेगे एवम् प्रार्थी को न्याय प्राप्ति से वंचित रह जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है एवम् सुविधा सन्तुलन भी पक्ष में साबित होता है एवम् अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी पर लागु होता है। जिससे उक्त परिस्थितियो में अप्रार्थीगण सह खातेदारो के विरुद्ध प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की भूमि में प्रार्थी के काश्त एवम् आवाजाही में किसी प्रकार से कोई रोक टोक, बाधा दखल करने से मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना नितांत आवश्यक एवम् न्यायसंगत है।




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 03 पर...

—कमश पेज(3) : निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0), देसूरी निर्णय राजस्व विविध संख्या-09/2020
द्वारा-212 आर.टी.एक्ट-प्रार्थी खीमाराम बनाम- अप्रार्थी मुराराम व अन्य.....

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवम् राजस्व अभिलेख जमाबन्दी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम सादडी-2 में स्थित खसरा नम्बर 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5186, 5188 कुल खसरे-9 कुल रकबा 3.2100 हैक्टर में विद्यमान प्रार्थी की खातेदारी के 1/8 हिस्से की भूमि में प्रार्थी के कब्जा काशत उपयोग उपभोग एवम् आवाजाही में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई रोक टोक, बाधा, दखल नही करे, ना ही किसी अन्य से करावे एवम् बिना विभाजन के वादग्रस्त आराजी की कोई भूमि विशेष को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, हस्तान्तरण, डेमेज नही करे एवम् अप्रार्थीगण उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न अपने परिवारजन मजदुरो, एजेन्टो या किसी अन्य से ही करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटीस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न बिन्दुओ पर विचारण किया गया—

प्रथम दृष्टया मामला — वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी स्वयं का 3/32 वा हिस्सा एवम् अपनी माता मृत होजी पत्नि जसा के नाम दर्ज 1/32 वा हिस्सा कुल मिला कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का 1/8 वा हिस्सा विद्यमान है। जिसके अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काशत मौके पर चला आ रहा है। किन्तु कानूनन बंटवाडा नही होने के कारण अप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर काशत करने तथा जमीन को खुर्दबुर्द करने हेतु आमादा है।

न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य अधिकार अभिलेख जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण सहखातेदार है। अतः सहखातेदार होने के सभी पक्षकारो का उक्त वादग्रस्त आराजी में समान हक अधिकार निहित है। तथा प्रार्थीगण ने अपने कब्जा काशत की भूमि पर दखलन्दाजी, आवागमन तथा अन्य को हस्तान्तरण करने से रोकने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 04 पर...


किये गये है जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्राथी के कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी में कहीं पर तथा किस ओर है तथा प्राथीगण और अप्राथीगण के मध्य आपसी समझाते से हुए बंटवाडा का उल्लेख कही नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया में यह ज्ञात होता है कि प्राथीगण और अप्राथीगण सयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्राथीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा सन्तुलन :- अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का सन्तुलन पर विचार किया गया। प्राथी एवम् अप्राथीगण रिकोर्डेड खातेदार है अतः सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर बराबर हक अधिकार है। अस्थाई निषेधाज्ञा यदि प्राथी के पक्ष में जारी कि जाती है तो अप्राथीगण को भी उतनी ही असुविधा होगी जितनी प्राथी को होगी। अतः उक्त बिन्दु प्राथी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूरणीय क्षति :- अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्राथी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्राथीगण प्राथीगण के बंट की कृषि भूमि पर नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवम् अप्राथीगण जमीन को अन्यत्र किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे प्राथीगण के हक अधिकारो को कुठाराघात होगा एवम् अनावश्यक वाद विवाद बड़ेगा। अप्राथीगण के इस कृत्य से प्राथीगण को अकथनीय क्षति होगी।

अपूरणीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। सहखातेदार के मध्य हुए बंटवाडे के संबंध में प्राथी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में अप्राथीगण के अलावा ओर भी पक्षकार हैं। अतिरिक्त पक्षकारो से विरुद्ध प्राथी ने किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है तथा ना ही अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाया है। जिससे प्राथीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो सभी पक्षकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा प्राथीगण वादग्रस्त आराजी में मौके पर कब्जे की स्थिति में संबंध में स्पष्ट नहीं होने से न्यायालय के मत में वादग्रस्त आराजी पर प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारो का सम्मान हक अधिकार है। जिससे सहखातेदारो के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की सकती है। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्राथीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दुओ प्राथी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है। अतएवं
पेज लगातार 05 पर...


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)


कमल घेज(6) : निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), देशूरी निर्णय राजस्व विविध संख्या-09/2020 धारा-212 आर.टी.
अप्रार्थी श्रीमाराम बनाम- अप्रार्थी भुराराम व अन्य.....


आदेश

प्रार्थीगण का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।


(राजलक्ष्मी गहलोट)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देशूरी (पाली)


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देशूरी (पाली)